राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1805/2013

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल, आनंद भवन, संसार चंद रोड, जयपुर-अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से।

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री अजय सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष,
2. मास्टर दौलत पुत्र स्वर्गीय श्री अजय सिंह, उम्र लगभग 10 वर्ष,
3. मास्टर कमल पुत्र स्वर्गीय श्री अजय सिंह, आयु लगभग 4 वर्ष,
4. मास्टर देवराज सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अजय सिंह, आयु लगभग 2 वर्ष,
5. श्री भोम सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पीरू जी, आयु लगभग 74 वर्ष (प्रतिवादी संख्या 2 से 4 तक का प्रतिनिधित्व प्राकृतिक अभिभावक उत्तरदाता संख्या 1 के माध्यम से किया जा रहा है) सभी निवासी इंद्रा कॉलोनी, ब्यावर रोड, मदुदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

----दावेदार/प्रत्यर्थीगण

6. विशाल सिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल कुंजियानिया निवासी टांक मोहल्ला, मसूदा अजमेर (मालिक)

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) के लिए : श्री रिजवान अहमद

प्रत्यर्थी (गण) के लिए : श्री जय प्रकाश गुप्ता के लिए श्री निशांत शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा

आदेश

रिपोर्टेबल

29/11/2021

1. यह अपील विद्वान् आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 अजमेर जिला अजमेर दिनांक 28.03.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत आयुक्त ने 4,19,840/- रुपये की राशि @ 12% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ, का पंचाट पारित किया है।

2. अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बीमा कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति को मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसकी मृत्यु दुर्घटना से संभावित न हो, लेकिन कुछ चोटों के कारण 10 महीने बाद मृत्यु हो गई है जो दुर्घटना के कारण साबित नहीं हुई है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बीमा कंपनी किसी भी तरह से नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को चुनौती नहीं देती है, लेकिन जहां तक मृतक का संबंध है, वह ड्रग्स की तस्करी में शामिल था और बीमित वाहन चलाते समय पुलिस द्वारा पकड़ा गया था और 03.06.2006 को गिरफ्तार किया गया था और 6 महीने तक जेल में रहा। दावेदारों ने एक मामला स्थापित किया है कि उसकी मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई चोटों से हुई थी जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। चोटें जारी रहीं जिसके लिए उनका इलाज चला और आखिरकार 10 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। अधिवक्ता ने कहा कि दुर्घटना से संबंधित कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है और न ही कोई दस्तावेजी सबूत दिखाया गया है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक को चोटें आईं। वास्तव में जिरह में, दावेदार ने स्वयं कहा है कि उसे नहीं पता कि चोटें दुर्घटना के कारण लगी थीं या पुलिस द्वारा पीटे जाने के कारण या जेल में रहते हुए गिरने के कारण। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चालक ने एक अविवेकपूर्ण कार्य किया है, इसलिए उसे मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए।

3. विद्वान अधिवक्ता 20.01.2015 को तय की गई ***प्रथम अपील संख्या 296/2013 में लक्ष्मणराव बनाम महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड*** के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया, जो ***1969 एसीजे 422*** में रिपोर्ट किए गए ***मैकिनन मैकेंज़ी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम इब्राहिम महमोद इस्साक*** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित पहले के निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आयुक्त सही परिप्रेक्ष्य में मामले की जांच करने में विफल रहे हैं और विकृत निष्कर्ष दिए हैं।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दुर्घटना किस तरीके से हुई होगी और किस तरह से चोट लगी थी, यह तथ्य का प्रश्न है। उन्होंने

एआईआर 2018 एससी 5593 में रिपोर्ट की गई ***उत्तर पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम बनाम श्रीमती सुजाता*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है।

5. मैंने प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. पुलिस ने मृतक अजय सिंह के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (15) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस को सूचना मिली कि वह जीप आरजे 01 टी 0744 में प्रतिबंधित सामग्री ले जा रहा है और उन्होंने आरोपी अजय सिंह द्वारा चलाए जा रहे वाहन को रोकने का प्रयास किया, जो पुलिस बैरिकेड पर नहीं रुका और पुलिस पर एक स्थानीय पिस्तौल से गोली भी चला दी। बाद में उन्हें उपरोक्त अपराधों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में रखा गया। कोई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं है और केवल यह सूचना है कि उनकी मृत्यु 15-04-2007 को हुई थी। 03-06-2006 को हुई घटना के संबंध में, यह एकमात्र दावेदार है जिसने मृतक के उपचार के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि चोटें उस समय लगी थीं जब वह पुलिस बैरिकेड से भागने का प्रयास कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप वाहन की दुर्घटना हुई थी।

7. प्रश्न उठता है कि क्या किसी वाहन के चालक की ओर से इस तरह का कृत्य उसे ड्यूटी के दौरान घायल होने के मुआवजे के अनुदान के उद्देश्य से कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के दायरे में लाएगा।

8. ***मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा.)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को निम्नानुसार उद्धृत करना उचित होगा:–

> "5. अधिनियम परिधि में आने के लिए दुर्घटना से होने वाली चोट रोजगार के दौरान और बाहर दोनों में उत्पन्न होनी चाहिए। "रोजगार के दौरान" शब्दों का अर्थ है "उस कार्य के दौरान जिसे करने के लिए कामगार को नियोजित किया जाता है और जो इसके लिए आकस्मिक है।
>
> "रोजगार से उत्पन्न" शब्दों का अर्थ यह समझा जाता है कि रोजगार के दौरान, सेवा के कर्तव्यों के लिए कुछ जोखिम आकस्मिक के परिणामस्वरूप चोट लगी है, जब, जब तक कि मास्टर के कारण कर्तव्य में संलग्न नहीं किया जाता है, यह विश्वास करना उचित है कि कामगार को अन्यथा नुकसान नहीं हुआ होगा।
>
> दूसरे शब्दों में, दुर्घटना और रोजगार के बीच एक कारण संबंध होना चाहिए।

"रोजगार से उत्पन्न" अभिव्यक्ति केवल रोजगार की प्रकृति तक ही सीमित नहीं है। अभिव्यक्ति रोजगार पर लागू होती है- इसकी प्रकृति, इसकी स्थितियों, इसके दायित्वों और इसकी घटनाओं पर। "यदि उन कारकों में से किसी के कारण कामगार को विशेष खतरे के क्षेत्र में लाया जाता है, तो चोट वह होगी जो "रोजगार से बाहर" होती है।

इसे अलग तरीके से कहें, तो यदि दुर्घटना हुई थी या किसी जोखिम के कारण जो रोजगार की घटना है, तो मुआवजे का दावा सफल होना चाहिए, जब तक कि निश्चित रूप से कामगार ने अपने स्वयं के अविवेकपूर्ण कार्य से खुद को एक अतिरिक्त खतरे में उजागर नहीं किया है। लंकाशायर और यॉर्कशायर रेलवे कंपनी बनाम हाईली 1917 ए.ओ. 362 लॉर्ड सुमनर में निम्नलिखित निर्धारित किया: यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कोई दुर्घटना "रोजगार से उत्पन्न हुई":

तथापि, मेरी राय में, एक परीक्षण है जो हमेशा किसी भी दर पर लागू होता है, क्योंकि यह कानून के शब्दों पर उत्पन्न होता है, और यह आम तौर पर कुछ वास्तविक सहायता का होता है। यदि यह है: क्या यह घायल व्यक्ति के रोजगार का हिस्सा था, खतरे में डालना, पीड़ित करना, या ऐसा करना जो उसकी चोट का कारण बना? यदि हां, तो दुर्घटना उनके रोजगार से उत्पन्न हुई। यदि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कुछ जोखिम उठाना, पीड़ित होना या करना रोजगार का हिस्सा नहीं था, वह रोजगार से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता है। यह पूछना कि क्या कामगार की दुर्घटना का कारण रोजगार के क्षेत्र में था, या रोजगार के सामान्य जोखिमों में से एक था, या रोजगार के लिए यथोचित आकस्मिक था, या इसके विपरीत, एक अतिरिक्त संकट था और रोजगार के क्षेत्र के बाहर, यह पूछने के सभी अलग-अलग तरीके हैं कि क्या यह उसके रोजगार का हिस्सा था, कि कामगार को वैसा ही कार्य करना चाहिए था जैसा वह कार्य कर रहा था, या उस स्थिति में होना चाहिए था जिसमें वह था, जिससे उस रोजगार के दौरान उसे चोट लग गई।

9. ***<u>लक्ष्मणराव (सुप्रा.)</u>*** के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय से प्रेरणा लेते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की:–

"7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में हुई घटना का मृतक कर्मचारी के रोजगार के साथ कोई संबंध था। इसके अलावा, अपीलार्थी ने यह भी दलील नहीं दी है कि जिस घटना के परिणामस्वरूप मृतक कर्मचारी की मृत्यु हुई, उसका मृतक के रोजगार के साथ कोई संबंध था। इस तथ्य के अलावा कि वन संरक्षक, नागपुर और अन्य बनाम कुसुमताई निवासी गणपतराव धोटे और अन्य के मामले में और महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अशोक कपशिकर और अन्य उन मामलों के तथ्यों पर आधारित हैं, मैकिनन मैकेंज़ी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम इब्राहिम महममोद

इस्साक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। इसी तरह, अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णय मैकिनन मैकेंज़ी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम इब्राहिम महमोद इस्साक के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर विचार करते हुए अपीलार्थी के लिए कोई सहायता नहीं हैं।

10. इस न्यायालय की राय में, उपरोक्त टिप्पणियों से विचलन का कोई कारण नहीं है। दावेदार यह भी साबित नहीं कर पाए हैं कि चोट तब लगी जब वह बीमित वाहन में प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहन का काम कर रहे थे। एक जीप का चालक जो पुलिस से बचने की कोशिश करने के लिए हथियार का उपयोग करता है और पुलिस बैरिकेड को भी तोड़ता है, उसे वाहन के चालक के रूप में सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

11. इसे ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत यथा परिकल्पित क्षतिपूत ऐसे व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह एक लाभकारी विधान है जो अपराध में संलिप्त व्यक्तियों की सहायता करने के लिए नहीं है।

12. वर्तमान मामले में, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मृतक की मृत्यु एक दुर्घटना के दौरान लगी चोटों के कारण हुई थी, वास्तव में वह लगभग 10 महीने की अवधि के बाद मर गया और बीच में 6 महीने तक जेल में रहा।

13. इसे ध्यान में रखते हुए, यह अदालत पाती है कि विद्वान् आयुक्त ने एक त्रुटि की है। ***पूर्वोत्तर कर्णाटक सड़क परिवहन निगम (सुप्रा.)*** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "9. प्रारंभ में, हम एक स्थापित सिद्धांत होने के नाते, इस तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हुआ, क्या दुर्घटना रोजगार के दौरान हुई, क्या यह रोजगार से उत्पन्न हुई, दुर्घटना कैसे और किस तरीके से हुई, दुर्घटना के कारण किसने लापरवाही की, क्या कर्मचारी और नियोक्ता का कोई संबंध था, कर्मचारी की आयु और मासिक वेतन क्या था, मृतक कर्मचारी के आश्रित कितने हैं, दुर्घटना में लगी चोटों के कारण कर्मचारी को हुई विकलांगता की सीमा, क्या घटना को कवर करने के लिए नियोक्ता द्वारा कोई बीमा कवरेज प्राप्त किया गया था, आदि कुछ भौतिक मुद्दे हैं जो आयुक्त के न्यायसंगत निर्णय के लिए उत्पन्न होते हैं। दावा याचिका जब किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान कोई शारीरिक चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है और वह अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए अपने नियोक्ता पर

मुकदमा करता है।

> 10. उपर्युक्त प्रश्न अनिवार्य रूप से तथ्य के प्रश्न हैं और इसलिए, उन्हें साक्ष्य की सहायता से साबित करने की आवश्यकता है। एक बार जब वे किसी भी तरह से साबित हो जाते हैं, तो उस पर दर्ज किए गए निष्कर्षों को तथ्य के निष्कर्ष के रूप में माना जाता है।

14. उपरोक्त से, यह सच है कि ये तथ्य के आवश्यक प्रश्न हैं कि दुर्घटना कैसे हुई और यह किस तरीके से हुई। हालांकि, यह कानून का प्रश्न बन जाता है कि क्या ड्यूटी के दौरान दुर्घटना हुई थी। इसलिए, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की दलील को खारिज कर दिया जाता है कि यह केवल तथ्य का एक शुद्ध प्रश्न है और यह अदालत अपील में इसकी जांच नहीं करेगी।

15. तदनुसार, इस न्यायालय ने पाया कि विद्वान् आयुक्त कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 द्वारा निर्णय पारित करते समय एक अवैधता की गई है और पारित निर्णय तदनुसार रद्द किए जाने के योग्य है।

16. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है। तदनुसार आयुक्त द्वारा पारित अधिनिर्णय को निरस्त किया जाता है। बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई राशि, यदि कोई हो, वापस कर दी जाएगी। बीमा कंपनी दावेदारों द्वारा प्राप्त राशि के लिए दावेदारों से वसूली कराने की भी हकदार होगी।

17. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

(संजीव प्रकाश शर्मा), न्यायमूर्ति

Karan/61

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।